

कायलिय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण किंग, राजस्थान, जयपुर।

परिषत्र नं० ४/२००३

विषय:- सार्वजनिक निर्माण विभाग को अधिकोष सम्पत्तियों के निस्तारण संबंधी ।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया के समक्ष प्रस्तुतोकरण के दौरान किंग द्वारा यह प्रोजेक्ट किया है कि वर्ष के दौरान 60-70 बड़ों ल्पये तक की सम्पत्तियों का निस्तारण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण किंग मंत्री महोदय ने यह निर्देश भी दिये हैं कि कई कस्बों एवं शहरों में विभाग के स्टोर इत्यादि शहरों के बीच स्थित हैं जहाँ भूमि को कोमत अच्छी है। विभाग के भड़ार घौकियों शहर के बाहर स्थित अन्य सरकारी भूमि पर स्थापित को जा सकती हैं। इसलिए ऐसी सम्पत्तियों को भी अब चिन्होकरण किया जाकर निस्तारण किया जाना होगा।

राज्य सरकार को उपरोक्त नोटि अनुसार आप कृपया ऐसी समस्त सम्पत्तियों का चिन्होकरण एक माह के अन्दर अन्दर करें। सम्पत्तियों के निस्तारण को किंगोय नीति पहले ही वित्त किंग से अनुमोदित है। जिन सम्पत्तियों का चिन्होकरण हो चुका हो उन्हें अगले 15 दिन के अन्दर-अन्दर संबंधित स्थानीय निकायों को निस्तारण हेतु सौंप दें। इस कार्य को प्रगति हेतु संबंधित छाण्ड के अधिकारी अभियन्ता उत्तरदायो होंगे और वे जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकायों से समर्थ कर हन सम्पत्तियों के त्वरित गति से निस्तारण हेतु प्रभावो बढ़ावा देंगे।

इन प्रकरणों को प्रगति को समोक्ता प्रति प्रशासन तथा सार्वजनिक निर्माण किंग को अधिकारी में होने वालो क्षेत्र में भी जाकेंगी।
कृपया इसे अति आवश्यक समझें।

मुख्य अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण किंग,
राजस्थान- जयपुर।

क्रमांक: एफ ७८३। } अनु०प्रधाम/ए/२००३/डो-१५०० दिनांक: २७ दिसम्बर, २००३

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ स्वं आवश्यक कार्यवाहो हेतु प्रेषित है:-

१- निजो तथि, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार सार्वजनिक निर्माण किंग, राजस्थान-जयपुर।

२- तथि, सार्वजनिक निर्माण किंग, राजस्थान, जयपुर।

३- शासन उप तथि, सार्वजनिक निर्माण किंग, राजस्थान, जयपुर।

४- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण किंग, समाज {समस्त}।

५- अधीक्षा अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण किंग, वृत्त {समस्त}।

६- अधिकारी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण किंग, छाण्ड {समस्त}।

७- वरि. निजो तहा. मु०अभि०/पथ/रा. ड. मा./अधी०अभि०{समस्त} } दूसरी

मु०अ०काय० के समस्त तैल/अनुभाग।

अधीक्षा तहांयक-पथम,
सार्वजनिक विभाग राज्य जयपुर